



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3—उपखण्ड—(i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216]
No. 216]नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2008/वैशाख 2, 1930
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2008/VAISAKHA 2, 1930

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2008

सा.का.नि. 300(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और 36 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 2008 है।

(2) ये 1 अगस्त, 1997 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 में नियम 12 में उप-नियम (2) में “प्रन्द्रह प्रतिशत” शब्दांशों के स्थान पर “तीस प्रतिशत” शब्दांश प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव के आधार पर उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के मकान किरायों भत्तों को 1 अगस्त, 1997 से संशोधित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 को भूतलक्षी प्रभाव से, अर्थात् 1 अगस्त, 1997 से संशोधित किया जा रहा है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण के किसी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[सं. ए-11014/3/08-ए.टी.]

डॉ. एस. के. सरकार, संयुक्त सचिव

टिप्पणियाँ : मूल नियम दिनांक 4-7-1986 के भारत के असाधारण राजपत्र-II, खण्ड 3(i) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधित किया गया :

1. सा.का.नि. 423(अ), दिनांक 4 अप्रैल, 1988
2. सा.का.नि. 32(अ), दिनांक 24 जनवरी, 1990
3. सा.का.नि. 500(अ), दिनांक 7 जून, 1994
4. सा.का.नि. 564(अ), दिनांक 8 सितम्बर, 1998
5. सा.का.नि. 289(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2002
6. सा.का.नि. 670(अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2007।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PERSONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2008

G.S.R. 300(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 35 and Section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Orissa Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Orissa Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2008.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 1997.

2. In the Orissa Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, in rule 12, in sub-rule (2), for the words "fifteen per cent", the words "thirty per cent" shall be substituted.

Explanatory Memorandum

On the basis of a proposal from the Government of Orissa, the Central Government has decided to revise the house rent allowance of Members of Orissa Administrative Tribunal with effect from the 1st August, 1997. Accordingly Orissa Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 are being amended retrospectively, that is with effect from 1st August, 1997.

It is certified that no Member of the Orissa Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the amendment being given retrospective effect.

[No. A-11014/3/08-AT]

Dr. S. K. SARKAR, Jt. Secy.

Notes : The principal rule was published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3(i) dated 4-7-1986 and the subsequently amended *vide* notifications No. :

1. G.S.R. 423(E), dated the 4th April, 1988
2. G.S.R. 32(E), dated the 24th January, 1990
3. G.S.R. 500(E), dated the 7th June, 1994
4. G.S.R. 564(E), dated the 8th September, 1998
5. G.S.R. 289(E), dated the 18th April, 2002
6. G.S.R. 670(E), dated the 18th October, 2007.